(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बनाये जाने वाले ऐसे प्रस्तावित होटलों की राज्य-वार सख्या कितनी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) और (ख). दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों (Metropolitan Cities) तथा चुने हुए अन्य पर्यटन केन्द्रों में सस्ते होटल बनाने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय क्षेत्र में निर्माण किये जाने वाले ऐसे होटलों की संख्या तथा स्थान इस बात पर निर्भर करेंगे कि छठी योजना के दौरान, जिस पर इस समय योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है, इस उद्देश्य के लिये कितने साधन उपलब्ध कराये जाते हैं । तथापि, भारत की यात्रा करने वाले वाले विदेशी पर्यटकों को दृष्टि में रखते हुए 5-स्टार वर्ग वाले होटलों की भी आवश्यकता है ।

केबल और कन्डक्टर का निर्यात करने वाले उत्पादकों द्वारा रियायतों की मांग

*361. **श्री उग्रसेन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को केबल और कन्डक्टर का निर्यात करने वाले उत्पादकों ने सरकार से कुछ रियायतें मांगी हैं और एल्यूमीनियम पर उत्पाद शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में अपना असन्तोष भी व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) और (ख). केबलों और कन्डक्टरों का निर्यात करने वाले विनिर्माताओं ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191(ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत एल्यूमीनियम की उत्पादन-शुल्क मुक्त सप्लाई की सुविधा एल्यूमीनियम के विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी । सरकार को यह भी बताया गया कि एल्यूमीनियम के विनिर्माताओं ने सप्लाई करने की अनिच्छा जाहिर की है । क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि उपरोक्त नियम 191(ख) के अन्तर्गत माल की सप्लाई करने पर अतिरिक्त उत्पादन पर 25 प्रतिशत की उत्पादन शुल्क राहत मिल जाएगी । तथापि, दिसम्बर, 1976 में राजस्व विभाग द्वारा स्वयं यह स्पष्टीकरण कर दिया गया कि उपरोक्त नियम के अन्तर्गत निकाला गया माल भी उत्पाद शुल्क राहत के हिसाब में शामिल किया जाएगा ।

पश्चिम एशिया के देशों में भारत में बनी प्लास्टिक की वस्तुओं की मांग

*362. **श्री नटरवरलाल बी० परमार** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया के देशों में भारत में बनी प्लास्टिक की वस्तुओं की भारी मांग है;

(ख) क्या ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान तथा अन्य देशों में प्लास्टिक की वस्तुओं की मांग और इन देशों को इन वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।